

“मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता”—देवेल फिलिप्स

**देनिक
भारतीय बस्ती**

सम्पादकीय

अब स्मृतियों में मनमोहन सिंह

देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब स्मृतियों में है। उन्होंने 92 वर्ष की उम्र में गुरुवार 26 दिसम्बर की रात्रि में अंतिम सांस ली। उन्होंने देश को दिवालिया बनने से बचाने के लिये ऐसी नीतियां बनायी जिससे सम्पद के रास्ते खुले और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उनका योगदान सदैव याद किया जायेगा। अपने वित्त मंत्री और 10 वर्ष के प्रधानमंत्री तकाल में डा. मनमोहन सिंह का योगदान भुलाया नहीं जा सकता। मनरेखा, सूचना का अधिकार, शिक्षा और भोजन का अधिकार देने सहित उन्होंने अनेक पहल कर गरीब और मध्यम वर्ग के मार्ग सुगम किये।

उन्होंने सिर्फ पीएम ही नहीं, प्रमुख अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री के रूप में भी अपनी सराएँ दी। भारत आज दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और जल्द इसके पांचवीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की उम्मीद है। जाहिर की यह रसी है, लेकिन 90 के दशक में हालात बिल्कुल विपरीत थी, उस समय देश में पीढ़ी नरसंघ राज की सरकार थी और वित्त मंत्री दिवंगत डॉ मनमोहन सिंह थे। ग्लोबल मार्केट में भारत की स्थिति निचले स्तर पर पहुंच चुकी थी। इंडियन करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले धराशायी हो गई थी और विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था, एक प्रकार से देश दिवालीया होने की कागर पर पहुंच गया था। लेकिन वित्त मंत्री ने देश के मिजाज को मनाया और कुछ ऐसे फैसले लिए जिससे भारत की तो तस्वीर ही बदल गई।

दिवंगत पर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साल 1991 से

१९९६ तारीख परिवर्तन के बाद लाइसेंस राजस्थान सरकार द्वारा १९९६ तारीख परिवर्तन के बाद लाइसेंस राजस्थान सरकार द्वारा भारी आर्थिक संकट की स्थिति में बड़े फैसले लेकर इकोनॉमी को संकट से निकाला था। इन कामों में पहला और सबसे बड़ा था लाइसेंस राजस्थान को खत्म करना। उन्होंने ऐसी नीतियाँ बनाईं, जिनके जरिए भारत के विदेशी निवेश के लिए जारी रखने की अपेक्षा गई। लाइसेंसी राज को खत्म करके आर्थिक उदारीकरण के नए युग की शुरुआत का श्रेय दिवारत मनमोहन सिंह को ही जाता है। आयात के लिए लाइसेंस को खत्म करना, ज्यादातर बिजनेस के लाभकारी रहा, वर्त्तोंके उनके लिए कई तरह के लाइसेंस लेने की वास्तविकता खल्म हो गई थी। इसके साथ ही विदेशी निवेश की वास्तविकता खल्म हो गई थी। लाइसेंस राज में तेजी से फॉरेंच इच्चेटटमेंट आने की शुरुआत हो गई। भारत में काम करने वाली कंपनियाँ अपना बाड़ा कारोबार कर रही हैं, जो विदेशी कंपनियाँ अपना बाड़ा कारोबार कर रही हैं, वो मनमोहन सिंह की ही देन हैं। उन्होंने कॉफीपॉर्ट टैक्स से लेकर इंपोर्ट शुल्क में कटौती समेत अन्य कई बड़े कदम उस समय बढ़ाए थे।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बड़े फसलों में अगला और अहम है अमेरिका के साथ भारत की न्यूट्रिलियर डील 2014 में राजस्थान के पोखरण देश के पहले परमाणु परीक्षण के बाद रिश्तों में तनाव देखने की मिला थी। जब मनमोहन सिंह साल 2004 में प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इन खराब हुए रिश्तों को सुधारने के लिए कदम आगे बढ़ाया। इस डील के लिए उन्हें यूपीए गठबंधन सरकार के सहयोगी लेपट का कड़ा विरोध भी झेलना पड़ा, लेकिन उन्होंने भारत-अमेरिका असेंयर परमाणु समझौते को आगे बढ़ावा दी कि फसला किया। आखिरकार अमेरिका से साथ ये ऐतिहासिक समझौता 2008 में हुआ। उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे। भारतीय में ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक सबबों के लिए एक मील का पथर साबित हुई। इसके जरिए दशकों से भारत के लिए बंद परमाणु ऊर्जा जलतों को पूरा करने के लिए अमेरिकी सहयोग का रास्ता फिर से ओपन हो गया।

मनमोहन सिंह के कार्यकाल के दौरान ही आधार कार्ड अस्तित्व में आया और ये दिव्यगत पूर्व पीएम की सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक बना। गैरतंत्रलव है कि इसे आधार कार्ड आज के समय में ही भारतीय की न केवल धनचान बन गया है, बल्कि तामाज़ काफी-सीधेयल कार्यों के लिए भी सबसे खलच्चर्य ढंगवुमेट हो गया है। जनवरी 2009 में देश के निवासियों को विशिष्ट धनचान प्रदान करने, विभिन्न सेवाओं तक पहुंच को सुविधानक बनाने के लिए आधार कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी।

मुफ्त की चुनावी घोषणाएं और अर्थव्यवस्था

— योगेन्द्र योगी—



कार्यपाल की सरकार बहाने पर हर परवियार को 100 शुद्धिकरण की विधि देने का गवादा किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री चिंगारी बहाने के तहत सभी कलारी बहाना योद्धाओं के खाते में एक हजार रुपये प्रति दिन कराया। करोनी ने बात किया था कि उसकी सरकार आई तो हजार नहीं बल्कि 1,500 रुपये दिये जाएंगे। चिंगारी ने मुद्राओं को लुप्तने के लिए 12वीं कक्ष के कुल 900 टीकरे को एक-एक स्कूटी देकर कालवर लिया था। चुनौती बहाना का कलवर चुरू से ही बदलवा से दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट, अधिकारी और इडियोमा, अधिक विशेषज्ञ, चुनाव आयोग और मौजूदा संसदीय नियन्त्रण मोदी तक इस पर दिया जाता है। यही जीर्णान्तिक विधि समझी की तरफ नहीं रही है।

वालिक
सुप्रीम
उत्तरां
कुण्डा कि
रेखोंडी
नुगान की
मारी की
जागरार
कोकिट
सुखुम्ब
उत्तरां को
लोगों
वाला
से पु
त्रां ए

अतिरिक्त स्थानिकरण नहीं रखता ऐस्या
माटी से कहा, यो भारतीय
टैक्सेप्रॉफ ई ऐसे लोग हैं जिन्हें
मुख्य विदेशी निम रख रहा है। यह
स्थिति गांधी विदार को बढ़ाव देती है। १५
वर्ष २०२२ में श्रीलंका का आर्थिक
सकट सामने आया तो इसने
दुनियावाली को अपनी कोरोना
सर्वदालूली बैठक में विदेश मंत्री एस.
जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका को
सबके लोग दुखी और मुस्त को कल्पना
से बचाना चाहिए। जयशंकर ने कहा
कि श्रीलंका जैसी स्थिति भारत
नहीं हो सकती, लिंगावहा से आगे
वाला सबके बहुत मजबूत है। इसके
लिए भी रेडी एक्सेप्लॉन एवं स्पाल
उत्तरां एवं पैरामोर्स में कहा था
कि अज्ञात हारे देश में मुकाबला
खेलने वालों के बाटों का कल्पना

देश के विकास के काम करते हैं। रेवेकी कल्पना जल्द ही कहती है कि जनता तक पहुँचने की रेवेकी बाटकर नहीं। मोटी ने कहा था कि रेवेकी कल्पना ने उसे इसी से बचा दिया। (राजीवीदा) और जनता भी आपको लेकिन उसके बावजूद चुनावों में फ्रीबीज का एलान होता ही रहा। इरजिं बैंक ऑफ इंडिया (राजीवीदा) ने कहा था, ऐसी याजनाएँ जिनसे क्रेडिट कर्तव्य

तुमानीन पर आर्थिक चुनौती वालायां की दो सारी तरफ से मारी जाती थीं तो शिलांग-में दिए गए और अपेक्षाकृत इसका प्रभाव करके था। इसका कारण बड़ी दिलचस्पी की वजह से भारतीय विदेशी व्यापारी आवासीय व्यापार की ओर आकर आई थी। वहाँ 2002 ईश्वरीय वर्ष के अंदर आर्योदाई की भी एक रिपोर्ट आई थी। इसके कारण गोप्य था कि राजनीतिक समूहों ने योग्यताएँ प्रदान करकर उसके लिए उपराजनकारी कर रही हैं। जिससे वो अपने के लिए भी फसली कर रही हैं। इसके दूसरे एक अद्वितीय रिपोर्ट दर्शाता है कि इस रिपोर्ट के अंत जापान राजनीति के नियन्त्रित थे। इनके बाद सरकारी विदेशी व्यापारी, करों और पर्यावरण बागल सम्बन्ध थे। तुमानी वादों के कारण इसके द्वारा मुद्रासंकेतीय अर्थ महाविहार भी था। अमेरिका ने पर घट रही है। राजनीतिक दिलचस्पी की इसके सरकारी नहीं है। सरकार में आने के बावजूद कामी

तो आनंदपुरा की
2006 के चुनावी
में सुमोहन कोट्टे
में सुमोहन कोट्टे
की जगह निर्वाचित
जब उसी लोगों को
उसी जगह और अंग
की जड़ को काफी
राजनीतिक पारियों से
एक एक आचार
क्रम बांट दिया गया।
जैसा कि इसके बारे में
विवरण दिया गया है।
इसके बारे में विवरण
दिया गया है।

विश्व युद्ध की आशका के बादल



—संजाप ठाफुर—

फुटपाथो और सड़को पर अतिक्रमण



—प्रयक्त सारम्—

नुच्छ बाजारा, नाम-बायारा, लिंगायती में दुकानदारों औं वैष्णवी-फौजी वालों की ओर से लिंगायती वालों वा अविक्रिया दिनानिवार बहाती ही था। परमाणुप्रवाप शरह के जागारों में बाहर चलाना तो दूर बढ़ लगाना भी मुश्किल ही गया। इस्टर्न ब्रिटिश जो आज जीवानिकारी लिंगायती अपने व्यापार पर निर्भर है, हर एक व्यापार जान के पास निर्दिष्ट नॉ-वॉ-डिंग जान पर विक्रियन कर लिया है, जिससे तात्पात्र बदलाव हो रहा है और अन्यायी दुकानदारों की ओर से लिंगायती वालों पर आ रही है। सार्वजनिक विकास विभाग ने लिंगायती वालों से सम्बन्धित ही समाजों में समाजों के लिंगायती वालों के बारे तरह दुख गैर-पीक घटी के दोषांश विभागों का अनुभवी दी या जाकर। सार्वजनिक सुरक्षा विभाग

विक्रीकारी की आधिकारिक कर्तव्यों की सीधी संतुलन बनाना एक नीतीकृत और प्रशासनिक व्युतीती है। स्टॉटर द्वारा या भर के शहरों में अधिकारिक स्थानों का एक अभिनन्दन आयोग जारी करने से यार्डमार्क खाली करने वाली शर्करा चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दुकानपारों के हितों की अनुचित लप्प से नुकसान न पहुँचाया जाए। जबकि अधिकारिक विक्रीकारी का शहर के लिए महत्वपूर्ण है, सामाजिक कल्याणीयों का यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टॉटर वेंडर जैसे कमज़ोर समूहों को अन्योपचारक नाम जाता है, लेकिन वे शहरी अर्थव्यवस्थाओं में हमच्छप्त होने वाली गतिहासी हैं। इन सीधी समी से यात्रावाले लोग स्टॉटर वेंडर हैं। नीपाचारिक अर्थव्यवस्था निगरानी के लिए न उन तरीकों का खुलासा करने वाले जिनसे स्टॉटर वेंडर अपने मुद्रावालों को माझबूत बना रहे हैं। स्टॉटर वेंडिंग रेसांग सुन्दर, उत्तम रूप से आवश्यक संरचनाएँ हैं। स्टॉटर वेंडर को कर्कश रूप से बदल दिया जाना, पुलिस कर्मियों और जननीयों और स्थानीय उपचारियों की समाप्ति करना एक सर्वानुभव का समाप्ति है।

जिसमें सभी लेखकों को तात्त्विकों का सम्बन्ध है। यही एकी समृद्धि का बाहर रखने से असत्तिक फैल सकती है। और प्रशासन को निष्पक्ष रूप से शासन करने की क्षमता पर भरपूर विद्युत देखने का मक्का हो सकता है।

शहरों की आवादी समय के साथ लगातार बढ़ती ही रही है। इनकी बढ़ती बाजारों की सच्चाया भी बड़ी रही है। लेकिन उनकी अधिकारीयता की सच्चाया भी जारी रही है। लेकिन उनकी अधिकारीयता की सच्चाया भी बड़ी रही है। और राजनीति के लिए लोगों का बहाव अब एक सिलसिला भी बढ़ा रहा है। लेकिन शहरों की बड़ी रही है। और अधिकारीयता के साथ नए रेखों और व्यापकतावान शासन की बढ़ती बाजारों की सच्चाया भी बड़ी रही है।

आधिकारीय रूप से कोर्टजर यक्ति नियन्त्रणकर्ता के लिए लोटी रूप निर्माण करता है। विकासों द्वारा की गई प्रतिस्पद और भौमिकाओं का नियन्त्रण करना दिक्षिण का नियन्त्रण करना उनकी भौमिका है।

परसन लाइन में यातायात का सुचारा वाला और सार्वजनिक सुचारा का व्यवस्थापकीय कानूनी जरूरी है। लेकिन उनकी लिये वाकातनी और डिकेंड समाज की वाकातनी सर्वजनिक व्यवस्था में नए रेखों और व्यापकतावान शासन की बढ़ती बाजारों की सच्चाया भी बड़ी रही है।

जिसमें सभी लेखकों को तात्त्विकों का सम्बन्ध है। एकी एकी समृद्धि का बाहर रखने से असत्तिक फैल सकती है। और प्रशासन को निष्पक्ष रूप से शासन करने की क्षमता पर भरपूर विद्युत देखने का मक्का हो सकता है।

शहरों की आवादी समय के साथ लगातार बढ़ती ही रही है। इनकी बढ़ती बाजारों की सच्चाया भी बड़ी रही है। लेकिन उनकी अधिकारीयता की सच्चाया भी बड़ी रही है। और राजनीति के लिए लोगों का बहाव अब एक सिलसिला भी बढ़ा रहा है। लेकिन शहरों की बड़ी रही है। और अधिकारीयता के साथ नए रेखों और व्यापकतावान शासन की बढ़ती बाजारों की सच्चाया भी बड़ी रही है।

आवाद्यकान होता है जो आधिकारीय व्यवस्थाका कल्पना दोनों पार व्याप के केंद्रित करता है। पैराम त्वनिवि योजना जैसे सरकारी कार्यक्रम के साथ सहायता प्रदान करता है जबकि रस्टें वैरेंट एवक, 2014 तक के अधिकारीयों की रक्षा करता है। बैंकों में कौशल विकास की पैकेज का अधिक विद्युत जन बाजारों और डिजिटल लेसेफर्मों को बढ़ावा देने से लियताओं का बहाव अब एक सिलसिला भी बढ़ा रहा है। लेकिन शहरों की बड़ी रही है। और अधिकारीयता के साथ नए रेखों और एकीकृत होने में घटना दियी रही है।

